

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

खुली बिड से उपापन

बिड नं०:- 01/2026

दिनांक:- 18-02-2026

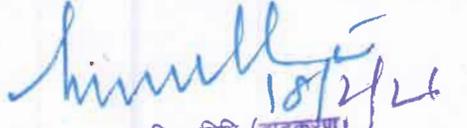
राजकीय वादकरण नीति, 2018 के तहत शासन सचिवालय, जयपुर में गठित विशेष प्रकोष्ठ हेतु सेवानिवृत्त जिला जज की सेवाओं का संविदा के आधार पर माह फरवरी, 2027 तक के लिए खुली बिड पद्धति से उपापन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

बिड की अवधि दिनांक 19.02.2026 से 25.02.2026 को सायंकाल 4:00 बजे तक है। बिड का UBN संख्या LDL2526SSOB00006 है।

विस्तृत बिड एवं प्रपत्रों के लिए बेब पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> विभागीय बेबसाईट <http://law.rajasthan.gov.in> देखें।

विशिष्ट शासन सचिव, विधि(वादकरण),
मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर। टेलिफोन नं० 0141-2227671

NIB - LDL2526A0006


विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजकीय वादकरण नीति, 2018 के तहत जयपुर में गठित विशिष्ट प्रकोष्ठ हेतु सेवानिवृत्त जिला जज की सेवाओं का संविदा के आधार पर माह फरवरी, 2027 तक लेने के लिए खुली बिड पद्धति से उपापन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

विस्तृत बिड एवं विस्तृत बिड एवं प्रपत्रों के लिए बेब पोर्टल <https://sppp.rajasthan.gov.in> विभागीय बेबसाईट <http://law.rajasthan.gov.in> देखें और डाउनलोड करें।

बिड का UBN संख्या LDL2526SS0800006 है।

उक्त सेवानिवृत्त जिला जज की सेवाएं राजकीय वादकरण विभाग के अधीन होगी और समय-समय पर उक्त प्रकोष्ठ के साथ-साथ नियंत्रक अधिकारी द्वारा अन्य कार्य भी लिए जा सकेंगे।

बिड में उपयुक्त पाये गये बिडर को स्वीकृति का पत्र (LOA) उपापन कर्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा और बिडर को अधिकतम 07 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण करना होगा। इसके अभाव में उपापन कर्ता अधिकारी बिना नोटिस जारी किये अन्य उपयुक्त बिडर को RTPP Act & Rules के अनुसार स्वीकृति का पत्र जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बिडर को मासिक उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जावेगा। समस्त राजकीय अवकाश स्वीकृत होंगे तथापि राजकार्य हेतु कार्यालय समय से पूर्व अथवा पश्चात् रोकने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। अवकाशों में भी बुलाया जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

अधिकतम 10 दिवस के आकस्मिक अवकाश पूर्व स्वीकृति के पश्चात् स्वीकार्य है अन्यथा स्थिति में अनुपातिक आधार पर भुगतान में कटौती की जावेगी। भुगतान की राशि बिड में अंकित करते समय यह ध्यान रखा जावे की वह दर समस्त करों सहित एवं जीएसटी यदि कोई हो अथवा भविष्य में लागू हो जावे तो उसे सम्मिलित माना जावेगा।

बिडर को उक्त राशि के अलावा किसी भी मद में अन्य किसी प्रकार का भुगतान यथा मोबाईल/टेलिफोन/इन्टरनेट/वाहन इत्यादि के लिए नहीं किया जावेगा।

राजकीय कार्य से यदि यात्राओं पर भेजा जावेगा तो बिडर को से0नि0 कार्मिकों के लिए बने नियमों के अनुरूप व्ययों का भुगतान किया जावेगा।


18/2/24
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

बिडर का नाम:

पता:

फोन नं०:

विशिष्ट शासन सचिव,

राजकीय वादकरण

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- राजकीय वादकरण नीति, 2018 के तहत गठित विशिष्ट प्रकोष्ठ हेतु से0नि0 जिला जज की सेवाओं का संविदा के आधार पर माह फरवरी, 2027 तक खुली बिड पद्धति से उपापन।

महोदय,

विषयान्तर्गत उपापन की विषयवस्तु के लिये पूर्ण बिड प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर कर एवं वांछित संलग्नकों सहित प्रस्तुत है। भुगतान की मासिक दर में समस्त कर एवं जी.एस.टी सम्मिलित है तथा स्रोत पर करों की कटौती के लिये मेरी सहमति है। अन्य किसी प्रकार की विधायी आवश्यकताओं में मेरी सहमति है।

मैंने बिड की समस्त शर्तों को पढ़ लिया हूँ एवं सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं। मेरी उक्त दरें दिनांक 28.02.2027 तक भान्य रहेगी। यदि सम्यक आवश्यकता हुई तो मैं इसे बढ़ाने की सहमति देने पर विचार कर सकता हूँ।

मुझे ज्ञान है कि मेरे प्रस्ताव को किसी भी स्तर पर रद्द करने के लिए उपापनकर्ता अधिकारी सक्षम एवं स्वतंत्र है।

भवदीय

बिडर का नाम एवं हस्ताक्षर

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

दिनांक:


18/2/26
विशिष्ट शासन सचिव (वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्श, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

बिडर को बिड के साथ बिड की स्वीकृति, बिडर का विवरण और विवरण में अंकित सूचना से संबंधित कागजातों की छायाप्रति उपलब्ध करवानी होगी। बिड प्रपत्र में मासिक भुगतान राशि का उल्लेख करना होगा। बिडर को यह स्वीकृति भी देनी होगी की उसकी बिड की वैधता दिनांक 28.02.2027 तक वैध रहेगी। बिडर को बिड में दिये गये सभी प्रपत्रों पर नीली स्याही में हस्ताक्षर करने होंगे। बिड में किसी भी प्रकार की कटिंग/ऑवर राईटिंग/तथ्यों की अलग-अलग अंकन की स्थिति में उपापनकर्ता अधिकारी बिड रद्द करने की शक्तियां रखते हैं।

बिड सिक्योरिटी के रूप में रूपये 7200/-की राशि जरिये डिमांड ड्रॉफ्ट अथवा ई-ग्रास चालान से बजट मद 8443-103 में जमा कराई जा सकती है। डिमांड ड्रॉफ्ट आहरण एवं वितरण अधिकारी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, वादरकण जयपुर के नाम देय होगा। ई-ग्रास द्वारा जमा करवाये जाने पर चालान की प्रति बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

सफल बिडर को कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत अनुबन्ध राशि (मासिक दर x 12 माह) का कुल 3 प्रतिशत जमा कराना होगा। यदि सहमति हो तो बिड प्रतिभूति के रूप में जमा राशि रूपये 7200/- का समायोजन करते हुए शेष राशि जमा कराई जा सकेगी। यदि यह राशि RTPP Act & Rules के अधीन सफलता पूर्वक अनुबन्ध समाप्ति पश्चात् नियमानुसार लौटाई जा सकेगी।

RTPP Act & Rules के प्रावधानानुसार Annexure A, B, C and D इस बिड प्रपत्र के भाग हैं और उनकी पालना सुनिश्चित कि जावे।

इस बिड प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/- एवं उस पर जीएसटी @18% राशि 90/- कुल राशि रूपये 590/- ई-ग्रास पर बिड प्रपत्र मूल्य की राशि में जमा करवाकर चालान की प्रति बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करें।


18/2/26
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (सादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

बिडर का नाम:

पता:

फोन नं०:

विशिष्ट शासन सचिव,
राजकीय वादकरण,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- राजकीय वादकरण नीति, 2018 के तहत गठित विशिष्ट प्रकोष्ठ हेतु से०नि० जिला जज की सेवाओं का संविदा के आधार पर माह फरवरी, 2027 तक खुली बिड पद्धति से उपापन।

महोदय,

विषयान्तर्गत उपापन की विषयवस्तु के लिये मैंने अपना सीलबन्द लिफाफे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं निम्न प्रकार घोषणा करता हूँ कि:-

1. समस्त सूचनायें एवं प्रपत्र सही हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जावे तो उसके लिये मेरा बिड प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है।
2. मेरे खिलाफ राजकीय सेवा संबंधित कोई भी शिकायत/वाद/जांच या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
3. वर्तमान में मैं किसी निजी या राजकीय सेवा में संलग्न नहीं हूँ।
4. मैं कोई निजी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ/मैं बिड में प्रस्तावित सेवायें ग्रहण करने से पूर्व निजी प्रैक्टिस बन्द कर दूंगा।

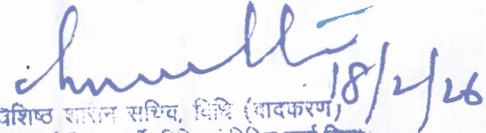
मैं स्वीकृति पत्र (LOA) प्राप्त होने के 07 दिवस में अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के साथ कार्यग्रहण कर लूंगा। अनुबन्ध की कार्यवाही का समस्त व्यय मेरे द्वारा किया जावेगा।

विभाग मेरे प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए मुझे बिना कारण बताये स्वतंत्र है। बिड आवेदन में समस्त मय मेरे द्वारा वहन किया जावेगा।

भवदीय

बिडर का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक:


विशिष्ट शासन सचिव, विशिष्ट (वादकरण)
संयुक्त विधि परवर्ती, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

बिडर का नाम:

पता:

फोन नं०:

विशिष्ट शासन सचिव,

राजकीय वादकरण,

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:- राजकीय वादकरण नीति, 2018 के तहत गठित विशिष्ट प्रकोष्ठ हेतु से0नि0 जिला जज की सेवाओं का संविदा के आधार पर माह फरवरी, 2027 तक खुली बिड पद्धति से उपापन के लिये मासिक दर का प्रस्ताव।

महोदय,

विषयान्तर्गत उपापन की विषयवस्तु के लिये मैंने अपना सीलबन्द प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं निम्न प्रकार घोषणा करता हूँ कि:-

1. समस्त सूचनायें एवं प्रपत्र सही हैं और यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जावे तो उसके लिये मेरा बिड प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है।
2. मेरे खिलाफ राजकीय सेवा संबंधित कोई भी शिकायत/वाद/जांच या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही लम्बित नहीं है।
3. वर्तमान में मैं किसी निजी या राजकीय सेवा में संलग्न नहीं हूँ।
4. मैं कोई निजी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ/मैं बिड में प्रस्तावित सेवायें ग्रहण करने से पूर्व निजी प्रैक्टिस बन्द कर दूंगा।

मैं इस बिड में रूपये /-(अक्षरे रूपये.....

.....), समस्त करों सहित एवं जी.एस.टी. सहित प्रतिमाह की दर पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं बिड में अंकित शर्तों के अध्यक्षीन यह दर भर रहा हूँ।

मैं बिड सिक्योरिटी के रूप में रूपये 7200/- (अक्षरे रूपये सात हजार दो सौ मात्र) का डिमांड ड्रॉफ्ट/ई ग्रास चालान सं०.....दिनांक....., जो कि आहरण एवं वितरण अधिकारी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, वादकरण जयपुर के नाम से कर रहा हूँ।

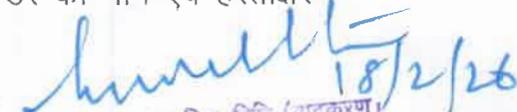
मैं स्वीकृति पत्र (LOA) प्राप्त होने के 07 दिवस में अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के साथ कार्यग्रहण कर लूंगा। अनुबन्ध की कार्यवाही का समस्त व्यय मेरे द्वारा किया जावेगा।

विभाग मेरे प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए मुझे बिना कारण बताये स्वतंत्र है। बिड आवेदन में समस्त मय मेरे द्वारा वहन किया जावेगा।

भवदीय

दिनांक:

बिडर का नाम एवं हस्ताक्षर


विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Annexure A : **Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest Any person participating in procurement process shall:-**

- [A] Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- [B] Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- [C] Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- [D] Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- [E] Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- [F] Not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- [G] Disclose conflict of interest, if any and.
- [H] Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict or interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:
 - A. Have controlling partners/shareholders in common or
 - B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - C. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - D. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - E. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - F. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
 - G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name


विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of.....in response to their Notice Inviting BidsDatedI/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, Financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition:

Date:

Signature or Bidder

Place:

Name

Designation:

Address:


18/2/24
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Annexure C:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the
First Appellate Authority

Secretary, Law & Legal Affair Deptt.
Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the
Second Appellate Authority

Principal Secretary, Law & Legal Affair Deptt.
Rajasthan, Jaipur

1) Filing an appeal:

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluated the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, and appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may fifteen days from the expiry of the period specified in the Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality;


18/2/26
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

5) **Forms of Appeal:-**

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondent in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6) **Fee for filing appeal:-**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) **Procedure for disposal of appeal:-**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Authority, as the case may be shall.
 - (2) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:

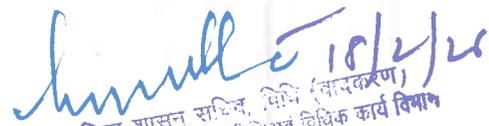
Signature or Bidder

Place:

Name

Designation:

Address:


विशिष्ट शासन सचिव, विधि (सावधान)
संयुक्त विधि परामर्श, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the.....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
.....
.....

Place.....

Date.....

Appellant's Signature

Handwritten signature
18/2/25
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वायकरण)
संयुक्त विधि परामर्श, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Annexure D:

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors:-

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis.

- i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- iii) If there is a discrepancy between and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award of procurement of Goods):-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered


विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर 18/2/24

that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature or Bidder

Name

Designation:


18/1/26
विशिष्ट शासन सचिव, विधि (आयकरणा)
संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधेक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Bid Detail

Department Details:	
Department Name	Litigation Department
Department Type	State Government Department
Procuring Entity Name:	Mr. Mahesh Punetha
Procuring Entity Contact:	Email: statelitigation[at]rajasthan[dot]gov[dot]in, Mobile: 9680879690
Office Address:	Law Litigation Department, Room No. 1001, Law And Legal Affairs Department (Litigation), Main Building, tilak marg, c-scheme, Jaipur, (Jaipur), PIN:302016, Landline No.:9413052505, Fax No.:

NIB Details:	
NIB Financial Year	2025 - 2026
NIB Code	LDL2526A0006
NIB Reference no	F12(8)RAJ/VAD/10 PART 1
NIB Publish Date	18/02/2026
Available for Public	18/02/2026 04:42 PM
NIB Published Bids	1 / 1
NIB Document	 [English n हिन्दी] 933.08 KB

Bid Details:	
UBN	LDL2526SSOB00006
Bid Title	REGARDING CONTRACTUAL SERVICES OF RETIRED DISTRICT JUDGES IN SPECIAL CELL LAW LITIGATION DEPARTMENT, SECRETARIAT
Bid Type	Services
Bid Sub Type	Consultancy Services
Bid Pattern	Open Competitive Bidding
Bid Amount	₹720000.00
Bid Required in Cover(s)	1
Bid Document	 [English n हिन्दी] 6.14 MB
First Appeal Hearing Authority	Secretary
Second Appeal Hearing Authority	Principal Secretary

Critical Dates:	
Bid Uploaded Date	18/02/2026
Bid Publish Date	18/02/2026
Available for Public Since Date	18/02/2026 04:42 PM
Bid Submission End Date	25/02/2026
Bid Open Date	26/02/2026